KHAN GLOBAL STUDIES
KGS Campus, Sai Mandir, Musallahpur Hatt, Patna - 6
Mob : 8877918018, 875735880

BPSC - Mains Que.

By : Karan Sir

बिहार मुख्य परीक्षा में राजव्यवस्था और संविधान से संबंधित संभावित प्रश्न
Possible questions related to Polity and Constitution in Bihar Main Exam

प्रश्न–1. भारतीय संविधान की प्रस्तावना, संविधान के दर्शन का सार है। टिप्पणी करें।

The Preamble of the Indian Constitution is the essence of the philosophy of the Constitution. make a comment.

प्रश्न–2. भूमंडलीकरण के दौर में सम्पूर्ण प्रभुत्व संपन्न की प्रासंगिकता की चर्चा कीजिए।

Discuss the relevance of absolute sovereignty in the era of globalization.

प्रश्न–3. समाजवाद को परिभाषित करते हुए बताए कि नई आर्थिक नीति किस प्रकार भारतीय समाजवाद के सामने एक खतरा है?

While defining socialism, explain how the new economic policy is a threat to Indian socialism?

प्रश्न–4. भारत में नागरिकों के मूल अधिकारों के संरक्षण में न्यायपालिका की क्या भूमिका है? उदाहरणों सहित चर्चा कीजिये।

What is the role of judiciary in protecting the fundamental rights of citizens in India? Discuss with examples.

प्रश्न–5. भारतीय संविधान में निहित 'समानता का अधिकार' एवं 'धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार' दोनों मौलिक अधिकार हैं, परंतु धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के प्रवेश संबंधी विवाद ने दोनों अधिकारों को एक द्वंद्व के बिन्दु पर ला खड़ा किया है, जिससे यह स्पष्ट कर पाना मुश्किल है कि क्या ये एक दूसरे के पूरक हैं या प्रतियोगी? टिप्पणी करें।

Both 'Right to Equality' and 'Right to Freedom of Religion' contained in the Indian Constitution are fundamental rights, but the controversy regarding women's entry into religious places has brought both the rights to a point of conflict, due to which it is difficult to clarify. The difficulty is whether they complement each other or compete? make a comment.

प्रश्न–6. भारतीय संविधान में वर्णित निदेशक तत्त्वों की विशेषताओं को बताएँ। किन आधारों पर इनकी आलोचना की जाती है? चर्चा कीजिये।

Explain the characteristics of the Directive Principles mentioned in the Indian Constitution. On what grounds are they criticized? Discuss.

प्रश्न–7. मौलिक अधिकार (FR) और नीति निदेशक सिद्धांतों (DPSP) के बीच प्रमुख अंतर क्या हैं। मौलिक अधिकारों (FR) और नीति निदेशक सिद्धांतों (DPSP) के बीच टकराव को दर्शाने वाले संबंधित मामलों पर चर्चा कीजिये।

What are the major differences between Fundamental Rights (FR) and Directive Principles of Policy (DPSP). Discuss related cases showing conflict between Fundamental Rights (FR) and Directive Principles of Policy (DPSP).

प्रश्न–8. 'आरक्षण की व्यवस्था' के हालिया स्वरूप को खत्म कर 'आर्थिक आरक्षण' देने की मांग किस हद तक उचित प्रतीत होती है? हालिया आंदोलनों के संदर्भ में कथन की चर्चा करें।

To what extent does the demand for abolishing the recent form of 'reservation system' and giving 'economic reservation' seem justified? Discuss the statement in the context of recent movements.

प्रश्न–9. सामाजिक–आर्थिक एवं राजनीतिक उन्नति के उद्देश्यों हेतु किया गया 'आरक्षण का प्रावधान' वर्तमान में केवल राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति का साधन मात्र बनकर रह गया है। कथन के संदर्भ में अनुच्छेद 340 की महत्ता व इससे संबंधित हालिया विवादों पर चर्चा करें।

The 'provision of reservation' made for the purposes of socio-economic and political progress has at present become only a means to fulfill political interests. In the context of the statement, discuss the importance of Article 340 and the recent controversies related to it.

प्रश्न–10. उन प्रणालियों पर चर्चा कीजिये जिनके माध्यम से भारतीय संविधान द्वारा कार्यकारी, विधायी एवं न्यायिक शाखाओं के बीच शक्तियों के पृथक्करण की व्यवस्था की गई है। मूल्यांकन कीजिये कि यह पृथक्करण भारतीय संदर्भ में संसदीय संप्रभुता पर नियंत्रण के रूप में किस प्रकार कार्य करता है।

Discuss the systems through which the Indian Con-

stitution provides for separation of powers between the executive, legislative and judicial branches. Evaluate how this separation acts as a check on parliamentary sovereignty in the Indian context.

प्रश्न–11. 'एक लोकतंत्र को तभी सफल और जीवंत माना जाता है जब उसके नागरिक, शासन में सक्रिय भाग लेने और देश के सर्वोत्तम हित के लिये जिम्मेदारियां संभालने हेतु तैयार हों' कथन के आलोक में मौलिक कर्त्तव्यों के महत्त्व को रेखांकित करें।

Underline the importance of fundamental duties in the light of the statement 'A democracy is considered successful and vibrant only when its citizens are ready to take active part in governance and assume responsibilities for the best interest of the country'.

प्रश्न–12. कई विशेषताओं और महत्त्वों के बावजूद संविधान में उल्लिखित मूल कर्त्तव्य आलोचना योग्य हैं। किन आधारों पर इनकी आलोचना की जा सकती है? चर्चा करें।

Despite many features and importance, the fundamental duties mentioned in the Constitution are worthy of criticism. On what grounds can they be criticized? Discuss.

प्रश्न–13. भारतीय संविधान में उल्लिखित केंद्र–राज्य वित्तीय संबंधों पर प्रकाश डालते हुए बताएँ कि जीएसटी ने इन संबंधों को किस प्रकार पुन: परिभाषित किया है?

Throwing light on the Centre-State financial relations mentioned in the Indian Constitution, explain how GST has redefined these relations?

प्रश्न–14. भारत में क्षेत्रवाद का आधार विभिन्न प्रकार की विविधता है। स्वतंत्रता के पश्चात् क्षेत्रवाद के कारण उभरने वाली समस्याओं का समाधान करने के लिए नियोजित प्रमुख साधन क्या हैं?

The basis of regionalism in India is diversity of various kinds. What are the major instruments employed to solve the problems arising due to regionalism after independence?

प्रश्न–15. क्षेत्रीय दलों के उदय होने से स्थानीय मुद्दे राजनीतिक विचार–विमर्श की मुख्यधारा में शामिल हुए हैं। क्या आपको लगता है कि एक साथ चुनाव (simultaneous election), स्थानीय मुद्दों की कीमत पर राष्ट्रीय स्तर के विचार–विमर्श का मार्ग प्रशस्त करेंगे ? चर्चा कीजिये।

With the rise of regional parties, local issues have entered the mainstream of political discussion. Do you think that simultaneous elections will pave the way for national level discussions at the expense of local issues? Discuss.

प्रश्न–16. राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की बढ़ती हुई भूमिका को स्पष्ट कीजिए।

Explain the increasing role of regional political parties in national politics.

प्रश्न–17. गठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री के कार्यों का विश्लेषण कीजिए।

Analyze the functions of the Chief Minister in the coalition government.

प्रश्न–18. राष्ट्रीय पार्टी प्रणाली के विखंडन की प्रक्रिया और अल्पमत या गठबंधन सरकारों के उद्भव ने भारतीय राजनीति और लोकतंत्र को कैसे प्रभावित किया।

How the process of fragmentation of the national party system and the emergence of minority or coalition governments affected Indian politics and democracy.

प्रश्न–19. चुनाव के परिप्रेक्ष्य में "स्टेट फंडिंग" से आप क्या समझते हैं? इसको लागू करने के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ कौन–सी हैं? इसको लागू करने के लिये कुछ व्यावहारिक व सर्वमान्य सुझाव दीजिये।

What do you understand by "State Funding" in the context of elections? What are the major challenges before its implementation? Give some practical and universally accepted suggestions to implement this.

प्रश्न–20. क्या निष्पक्ष, न्यायोचित और खुले चुनाव सुनिश्चित करने में चुनावी बांड प्रभावी हैं? चुनावी बांड से जुड़ी विभिन्न चिंताओं पर चर्चा कीजिये।

Are electoral bonds effective in ensuring fair, equitable and open elections? Discuss the various concerns related to electoral bonds.

प्रश्न–21. दबाव समूहों से आप क्या समझते हैं? दबाव समूह पिछड़े लोगों के हितों को कैसे प्रतिबिंबित कर रहे हैं?

What do you understand by pressure groups? How are pressure groups reflecting the interests of backward people?

प्रश्न–22. दबाव समूह, राजनीतिक दलों से किस प्रकार भिन्न हैं? "राजनीतिक दलों की निष्क्रियता से उपजा निर्वात ही दबाव समूह की उत्पत्ति का कारण है।" इस कथन पर चर्चा करें।

How are pressure groups different from political parties? "The vacuum created by the inaction of political parties is the reason for the origin of pressure groups." Discuss this statement.

प्रश्न–23. दलबदल विरोधी कानून का नेक मकसद सरकारों में स्थिरता लाना है। हालाँकि इसे कभी–कभी लोकतंत्र की मूल भावना के विरुद्ध भी कहा जाता है। चर्चा कीजिये।

The noble objective of anti-defection law is to bring stability in governments. However, this is sometimes said to be against the basic spirit of democracy. Discuss.

प्रश्न–24. दल–बदल की राजनीति को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा करें। क्या ये प्रावधान अपने उद्देश्यों में सफल रहे हैं?

Discuss the constitutional provisions governing anti-party politics. Have these provisions succeeded in their objectives?

प्रश्न–25. क्या न्यायिक सक्रियता ने भारत में संसदीय लोकतंत्र को कमजोर बना दिया है? विवेचना कीजिए।

Has judicial activism weakened parliamentary democracy in India? Please discuss.

प्रश्न–26. भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न ऐतिहासिक फैसलों में राजद्रोह कानून की व्याख्या किस प्रकार की है? भारत में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर इन फैसलों के प्रभावों का विश्लेषण कीजिये। क्या आपको लगता है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में राजद्रोह कानून वर्तमान में भी प्रासंगिक है? अपने उत्तर के कारण भी बताइये।

How has the Supreme Court of India interpreted the sedition law in various landmark judgments? Analyze the effects of these decisions on freedom of speech and expression in India. Do you think the sedition law is still relevant in a democratic country like India? Also give reasons for your answer.

प्रश्न–27. शहरी स्थानीय निकाय (ULBs) एक ऐसे बिंदु पर खड़े हैं जिससे इनके व्यापक सुधार की मांग परिलक्षित होती है। ULBs के सुचारू कार्य संचालन में विद्यमान प्रमुख चुनौतियों को बताते हुए इन्हें दूर करने के उपाय बताइये।

Urban local bodies (ULBs) are at a juncture that demands comprehensive reforms. Explain the major challenges present in the smooth functioning of ULBs and suggest ways to overcome them.

प्रश्न–28. पंचायत विस्तार सेवा अधिनियम (PESA), 1996 के उपबंधों का परीक्षण कीजिए।

Examine the provisions of the Panchayat Extension Services Act (PESA), 1996.

प्रश्न–29. पंचायती राज संस्थान अभी भी राज्य के नियंत्रण एवं नौकरशाह के प्रभुत्व से ग्रस्त है। अपने कथन के पक्ष में तर्क दीजिए।

The Panchayati Raj institution still suffers from state control and bureaucratic dominance. Give arguments in favor of your statement.

प्रश्न–30. पंचायती राज संस्था हमेशा से वित्तीय स्वायत्तता के आभाव और धन की कमी से पीड़ित रहा है। व्याख्या कीजिए।

The Panchayati Raj institution has always been suffering from lack of financial autonomy and shortage of funds. Explain.

प्रश्न–31. डिजिटल युग में ऑनलाइन मुक्त भाषण (Online free speech) के निहितार्थों पर चर्चा कीजिये। लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका को बताते हुए इसके विनियमन एवं शासन के समक्ष इससे उत्पन्न चुनौतियों का परीक्षण कीजिये।

Discuss the implications of online free speech in the digital age. Examine the challenges it poses to its regulation and governance while explaining its role in promoting democratic values.

प्रश्न–32. राज्यपाल 'राज्य का संवैधानिक प्रमुख' होने के बजाय 'केंद्र का एजेंट' मात्र होता है। भारत में राज्यपाल के पद से जुड़े हाल के विवादों की चर्चा कीजिये।

Instead of being the 'constitutional head of the state', the Governor is merely an 'agent of the Centre'. Discuss the recent controversies related to the post of Governor in India.

प्रश्न–33. औपचारिक प्रमुख होने के बावजूद भारतीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति की महत्त्वपूर्ण भूमिका है।" टिप्पणी करें।

Despite being the formal head, the President plays an important role in the Indian governance system." make a comment.

प्रश्न–34. अभिशासन के एक महत्त्वपूर्ण उपकरण के रूप में ई–शासन ने सरकारों में प्रभावशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेयता का आगाज कर दिया है। कौन–सी अपर्याप्तताएँ इन विशेषताओं की अभिवृद्धि में बाधा बनती हैं?

E-governance as an important tool of governance has ushered in effectiveness, transparency and accountability in governments. What inadequacies hinder the development of these characteristics?

प्रश्न–35. विधायी कार्यों के संचालन में व्यवस्था एवं निष्पक्षता बनाए रखने में और सर्वोत्तम लोकतांत्रिक परंपराओं को सुगम बनाने में राज्य विधायिकाओं के पीठासीन अधिकारियों की भूमिका की विवेचना कीजिये।

Discuss the role of the presiding officers of state legislatures in maintaining order and fairness and facilitating the best democratic practices in the conduct of legislative business.

प्रश्न : संसदीय संप्रभुता के प्रति ब्रिटिश और भारतीय दृष्टिकोणों की तुलना करें और अंतर बताएँ।

Compare and contrast the British and Indian approaches to parliamentary sovereignty.

प्रश्न–36. संसदीय समितियाँ भारतीय लोकतंत्र का एक अनिवार्य हिस्सा हैं, जबकि उन्हें अपने कामकाज में कई चुनौतियों और सीमाओं का सामना करना पड़ता है। भारतीय संसदीय समितियों की भूमिका और चुनौतियों पर चर्चा कीजिये।

Parliamentary committees are an essential part of Indian democracy, while they face many challenges and limitations in their functioning. Discuss the role and challenges of Indian parliamentary committees.

प्रश्न–37. भारतीय निर्वाचन प्रणाली में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (आरपीए अधिनियम, 1951) के महत्त्व और इसकी समकालीन प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिये। इसमें हुए विभिन्न संशोधनों और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों के संचालन पर उनके प्रभाव का विश्लेषण कीजिये।

Discuss the importance of the Representation of the People Act, 1951 (RPA Act, 1951) in the Indian electoral system and its contemporary relevance. Analyze the various amendments made in it and their impact on the conduct of free and fair elections.

प्रश्न–38. वर्तमान में बिहार सरकार द्वारा संपन्न जातिगत जनगणना के कारण केंद्र एवं राज्य के बीच विवाद शुरू हो गए। जातिगत जनगणना कराने के पीछे बिहार सरकार की कारणों का अवलोकन करते हुए बिहार एवं भारत की राजनीति में जातिगत जनगणना की जरुरत क्यों है? इसकी विवेचना कीजिए।

Presently, due to the caste census conducted by the Bihar government, disputes started between the Center and the state. Considering the reasons of Bihar government behind conducting caste census, why is there a need for caste census in the politics of Bihar and India? Discuss this.

प्रश्न–39. क्षेत्रीय सरकारे जाति को राजनीतिकरण का मूर्त रूप देने में संलग्न है। इससे संघवाद कैसे प्रभावित होगा?

Regional governments are engaged in giving concrete shape to the politicization of caste. How will this affect federalism?

प्रश्न–40. जातिगत जनगणना क्या है? इसकी आवश्यकता क्यों है?

What is caste census? Why is it needed?

❑❑❑

KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR